International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.170-172

गाँधीवादी अर्थव्यवस्था : समकालीन विश्व में प्रासंगिकता

डॉ. सर्वेश कुमार*

प्रस्तावना

दुनिया ने अलग–अलग दौर में विभिन्न आर्थिक मॉडल देखें हैं, किंतु गाँधी मॉडल विशिष्ट है। चाहे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्तर पर आकर दुनिया ने इन आर्थिक मॉडल्स का अधूरापन देखा है। दुनिया में जितने भी आर्थिक मॉडल हुये हैं, उनके केन्द्र में भौतिक विकास रहा है। गाँधी का आर्थिक मॉडल नैतिक विकास पर बल देता है। सत्य और अहिंसा का विचार गाँधी के हर विचार के केन्द्र में है। गाँधी एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण के पक्षधर थे, जो व्यक्ति को अधिकाधिक स्वावलंबी बनाती हो। आर्थिक विकास का गाँधीवादी मॉडल ही सच्चे अर्थों में समावेशी मॉडल है, क्योंकि गाँधी का मत है कि अंतिम स्थिति में बैठे व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। जिसे गाँधी अंत्योदय कहते हैं।[1] गांधी के आर्थिक मॉडल के साथ एक अन्य बात महत्त्वपूर्ण रूप से जुड़ती है और वह यह है कि "गाँधी का आर्थिक मॉडल पर्यावरण मित्र है।" गाँधी ऐसे विकास के विरोधी थे जो पर्यावरण को क्षति पहुँचाकर हासिल किया गया हो। आज दुनिया में पर्यावरण मित्र विकास की जो बहस चल रही है उसका आधार गाँधी चिंतन में तभी स्थापित हो गया था, जब गाँधी ने कहा कि–"इस पृथ्वी के पास हमारी जरूरतें पूरा करने की पूरी क्षमता है, किंतु लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती।" अध्ययन में पर्यावरण मित्र विकास व सतत् विकास आदि शब्द बाद में विकसित हुए हैं, किंतु धारणीय विकास का भाव गाँधी चिंतन में बहुत पहले ही आ गया था।

गाँधी कुटीर उद्योग और विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के बहुत हिमायती थे। कुटीर उद्योग और विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था परस्पर पूरक हैं। गाँधी का मत है–आर्थिक संसाधनों पर कुछ हाथों का ही नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अपितु इसका नियंत्रण एवं प्रसार सुदूर क्षेत्र में रह रहे लोगों तक होना चाहिए। आर्थिक केन्द्रीकरण शोषण एवं अन्याय का कारण बनता है। दुनिया में भी आर्थिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। वैश्विक स्तर पर पूंजी और तकनीक के एक बड़े हिस्से पर पश्चिम के चुनिंदा देशों का नियंत्रण है। पश्चिम के पूंजीवादी देश गरीब विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। विकासशील देशों की नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग वास्तव में दुनिया की विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की मांग है। गाँधी कुटीर उद्योगों के बड़े हिमायती थे, इस से अर्थव्यवस्था तो विकेन्द्रित होती है, साथ में आर्थिक स्वावलंबन भी बढ़ता है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु निर्देशित किया गया है। यह अलग बात है कि वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण और निजीकरण के दौर में दुनिया भर के कुटीर उद्योग दम तोड़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने दुनियाभर के उत्पादन, पूंजी व उन्नत तकनीक पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इससे लोगों और परस्पर देशों के मध्य आर्थिक असमानता बढ़ी है, और इससे समावेशी विकास का लक्ष्य पीछे जा रहा है।

बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में गाँधी का स्वदेशी का विचार पीछे चला जा रहा है। यद्यपि स्वदेशी का विचार आज भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान था। स्वदेशी का विचार विकासशील और अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था के संरक्षण में और भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। स्वदेशी से स्वावलंबन और स्वाभिमान का विकास होता है। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भी वही राष्ट्र शक्तिशाली समझा जाता है, जो

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद, राजस्थान।

अधिकांश मामलों में आत्मनिर्भर होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ ब्रिटेन जैसा देश यूरोपीय संघ से बाहर जा रहा है। अमेरिका मैक्सिको के साथ दीवार खींचना चाहता है, तो चीन और यू.एस.ए. ट्रेड वार में व्यस्त है। आज आर्थिक संरक्षणवाद का रास्ता वही देश बता रहे हैं, जो किसी दौर में वैश्वीकरण के पैरोकार थे।[2] बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में विकासशील देशों को अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों को बचाना होगा तभी विकास अंतिम व्यक्ति के जीवन को रोशन कर पायेगा। जिस तरह राष्ट्रीय आन्दोलन ने उपनिवेशवाद को कमजोर किया था, उसी तरह दुनिया के देशों को स्वदेशी पर बल देकर नवउपनिवेशवाद का उन्मूलन करना है।

गाँधीवादी अर्थव्यवस्था में बड़ी मशीनों के लिए कोई स्थान नहीं है। गाँधी मानते हैं कि बड़ी मशीनों से उत्पादन कार्य और पूंजी का केन्द्रण सीमित हाथों में हो जाता है और यह संकेन्द्रण समाज में आर्थिक विषमता और शोषण का कारण बनता है। गाँधी छोटी मशीनों का विरोध नहीं करते थे। गाँधी का चरखा स्वयं एक मशीन है। गाँधी मानते हैं कि जो मशीन मानव श्रम का स्थान नहीं लेती है, उसमें कोई बुराई नहीं है।[3] बड़ी मशीनों से हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यही वजह है कि भारत में लागू की गई महत्त्वाकांक्षी 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में बड़ी मशीनों को कार्य की अनुमति नहीं दी गई है। गाँधीवादी अर्थव्यवस्था को नगरीकरण के विकास का सूचक नहीं माना गया है। गाँधी, अर्थव्यवस्था का केन्द्र गांवों को रखना चाहते थे। गांवों को आत्मनिर्भर गणराज्य के रूप में स्थापित करना, गाँधी का लक्ष्य था। बाद में दुनिया ने नगरीकरण के दुष्परिणाम देखे हैं। सबसे बड़ी मलिन बस्तियाँ सबसे बड़े महानगरों में मिलती है। नगरीय जीवन में भौतिकवाद इस कद्र बढ़ गया है कि नैतिक व्यवहार का स्थान सिमटता जा रहा है। बालश्रम यौन अपराध, कालाबाजारी, घरेलू हिंसा, सफेद पोश अपराध नगरीय जीवन की पहचान बन गये हैं। ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं होने से गांवों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। रोजगार की तलाश में जनता गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रही है।

न्यास या प्रन्यास सिद्धान्त गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का नायाब सिद्धान्त है। न्यास सिद्धान्त के द्वारा गाँधी ने पूंजीपतियों को संदेश दिया कि–"वे अपने पास जमा पूंजी को समाज की धरोहर समझे।" पूंजीपतियों को समय–समय पर जनोपयोगी कार्यों में आर्थिक सहयोग करते रहना चाहिए। गाँधी का प्रन्यास सिद्धान्त पूंजीवाद और साम्यवाद के संघर्ष के बीच से समाधान प्रस्तुत करता है।[4] गाँधी सामाजिक–आर्थिक समानता के उतने ही बड़े पक्षधर रहे हैं, जितने कार्ल मार्क्स हैं, किंतु गाँधी पूंजीवादी के उन्मूलन की बजाय उसमें संशोधन का रास्ता खोलते हैं, जबकि मार्क्स को पूंजीवाद से कोई उम्मीद नहीं थी। मार्क्स का आदर्श समाज, पूंजीवाद के उन्मूलन से ही संभव है। गाँधी ने प्रन्यास सिद्धान्त को व्यवहार में लागू करके भी दिखाया। ऐसे बहुत से पूंजीपति थे, जो राष्ट्रिय आन्दोलन में गाँधी के अनुयायी बने और आर्थिक सहयोग भी किया। बड़े उद्योगपति जमनालाल बजाज तो गाँधी के पाँचवें पुत्र कहलाते थे। आज भी दुनिया में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, विनोद खोसला, डेविड रॉकफेलर, शिव नाडार, अजीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति हैं, जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में खर्च करते हैं। भारत सरकार ने भी वर्ष 2013 में कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सबिलिटी (Corporate Social Responsibility) कानून पारित किया है, इसके तहत् एक कम्पनी को अपनी कुल शुद्ध आय का कम से कम 2 प्रतिशत भाग सामुदायिक कार्यों पर खर्च करना होगा।[5] यह कानून गाँधी के न्यास सिद्धान्त से काफी मिलता–जुलता है। यद्यपि गाँधी किसी पूंजीपति को सामुदायिक सहयोग करने हेतु बाध्य करने के पक्षधर नहीं थे। गाँधी का पूरा आर्थिक चिंतन सत्य, अहिंसा और हृदय परिवर्तन पर टिका है। आज दुनियाभर में पूंजीपति आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित किए बैठे हैं, दूसरी ओर दुनिया की बड़ी आबादी नारकीय जीवन जी रही है। ऐसे में गाँधी का न्यास सिद्धान्त प्रासंगिक हो उठता है, ताकि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक विश्व का निर्माण संभव हो सके।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा गाँधीवादी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था अपेक्षित रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है, अपितु साल दर साल बेरोजगारी दर बढ़ी रही है। जापान, कोरिया आदि कुछ देशों को अपवाद मान लें तो दुनियाभर में स्कूली शिक्षा महज किताबी शिक्षा बनकर रह गई है। आज युवाओं के

पास डिग्रियाँ तो हैं किंतु कुशलता नहीं है। यही वजह है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गाँधी की बुनियादी शिक्षा बालक को किताबी शिक्षा के साथ–साथ हाथ का काम भी सिखाती है ताकि बालक आगे चलकर बेरोजगार नहीं रहे। हुनरमंद बालक उत्पादन को बढ़ता है और कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनता है। आज की दुनिया के आर्थिक मॉडल में कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा हैं। अतः आज वैश्विक बेरोजगारी से निपटने के लिए गाँधी के बुनियादी शिक्षा के विचार को दुनिया के देशों को लागू करना होगा।

श्रम की गरिमा और कायिक श्रम पर गाँधी ने काफी बल दिया है। गाँधी किसी काम को छोटा–बड़ा नहीं मानते थे, उनकी नजर में शौचालय सफाई का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण और पवित्र है, जितना पूजा–उपासना का कार्य है। हर तरह के श्रम को समाज में गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए। यदि एक मेहतर गंदगी नहीं उठायेगा तो समाज सड़ उठेगा। गाँधी इस बात पर भी बल देते हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों को श्रम करने का अवसर मिलना चाहिए। जाति और लैंगिक आधार पर हम किसी को श्रम में भागीदार होने से नहीं रोक सकते। दूसरा गाँधी कायिक श्रम के हिमायती थे अर्थात् किसी भी व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय कुछ भी क्यों न हो किंतु उसे प्रतिदिन इतना शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए, जितना वह दिन में अन्न ग्रहण करता है। आज जीवन शैली से जुड़ी बहुत–सी बिमारियाँ इसीलिए पनप रही हैं, क्योंकि लोगों ने कायिकश्रम करना छोड़ दिया। आज कायिक श्रम वही लोग कर रहे हैं जिनके लिए ऐसा करना मजबूरी है। दुनिया में आज भी बहुत से पिछड़े एवं विकासशील देश हैं जहाँ श्रम की गरिमा को लागू नहीं किया जाता है। महिलायें घर से बाहर का कार्य नहीं करेंगी अपितु पर्दे में रहेंगी आदि घटनाओं से उत्पादन में पूरे समाज का सहयोग नहीं मिल पाता है। इससे समावेशी और धारणीय विकास भी तय नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुत–सी चुनौतियों का हल गाँधी चिंतन में निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- महात्मा गाँधी, सर्वोदय (अन टू द लास्ट), नवजीवन ट्रस्ट प्रकाशन।
- ओम प्रकाश गाबा, भारतीय राजनीतिक विचारक, मयूर बुक्स प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष 2018.
- अमरीका–चीन ट्रेड वारः पाँच अहम बातें, बीबीसी न्यूज, 12 मई, 2019.
- महात्मा गाँधी, 'हिन्द स्वराज' पुस्तक, प्रभात प्रकाशन–1 जनवरी, 2010.
- Corporate Social Responsibility-Indian Companies Act, 2013.

❖◆❖